



‘इण्डो- यूएस ट्रेड डील पर चार-पांच दिन में दोनों देश संयुक्त बयान देंगे’

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि संयुक्त वक्तव्य के बाद वाइट हाउस के एग्जीक्युटिव आदेश से यूएस टैरिफ घटकर 18 प्रतिशत रह जाएगा

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 05 फरवरी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि अमेरिका-भारत व्यापार समझौते का पहला चरण लगभग तैयार है और दोनों देश चार-पांच दिनों में संयुक्त बयान जारी करेंगे। सोमवार रात अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा दृथ सोशल पर की गई घोषणा के बाद दिल्ली और वाशिंगटन के बीच समझौते की पहली जानकारी सामने आने लगी है।

गोयल ने कहा कि संयुक्त बयान के बाद वाइट हाउस के कार्यकारी आदेश के जरिए अमेरिकी टैरिफ 18 प्रतिशत तक कम हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर करने में 30-45 दिन लगेंगे और इसे मार्च में साइन किया जाएगा।

- पीयूष गोयल ने बताया कि औपचारिक एग्रीमेंट होने में 30 से 45 दिन लगेंगे और संभवतया मार्च तक एग्रीमेंट हो जाएगा और इस पर मार्च में वर्चुअली साइन किये जाएंगे।

- ट्रंप ने ट्रेड डील की घोषणा सोमवार रात की थी जिसमें यह भी कहा था कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा। इसे स्पष्ट करते हुए वाणिज्य विभाग के अफसरों ने बताया कि विमान खरीद के ही ऑर्डर 70-80 अरब डॉलर के होंगे। भारत ईंधन, विमान व चिप्स खरीद पर 300 अरब डॉलर खर्च करेगा।

- वेनेजुएला से ईंधन खरीदने के ट्रंप के दावे पर विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, वेनेजुएला हमारा पुराना सहयोगी है, हम उससे तेल खरीदते रहे हैं। पर प्रवक्ता ने रुस से तेल खरीद के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा।

उन्होंने बताया कि संयुक्त समझौते पर वर्चुअल तरीके से हस्ताक्षर किए जाएंगे और संयुक्त बयान के बाद कार्यकारी आदेश के जरिए भारत से आने वाले सामान पर अमेरिकी शुल्क 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा।

गोयल ने कहा, “हम चाहते हैं कि समझौता जल्दी हो, क्योंकि इसके बाद हमें और रियायतें मिल सकती हैं।”

वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा, “मार्च में लीगल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत अमेरिका के सामान पर शुल्क कम करेगा।”

ट्रम्प के इस दावे पर भी कुछ स्पष्टता सामने आई कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा।

व्यापार अधिकारियों ने बताया कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

व्हीलचेयर पर संसद पहुंचे थरुर

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 5 फरवरी। संसद के मकर द्वार से व्हीलचेयर से गुजरते हुए, शशि थरुर ने कहा कि वह संसद में अपने कर्तव्यों और केरल में अपने चुनावी कार्य को जारी रखेंगे। ज्ञातव्य है कि बुधवार को थरुर संसद भवन में गिर गए इस कारण उनके पैर में एक हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया है।

पत्रकारों से बात करते हुए, तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस के सांसद थरुर ने कहा कि उनका पैर कास्ट में रहेगा और ठीक होने में कम से कम 4-6 सप्ताह लगेंगे। थरुर ने कहा, “मैं

- कांग्रेस के सांसद शशि थरुर बुधवार को संसद की सीढ़ियों से लड़खड़ाकर गिर गए थे, उनके पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर है।

अपना काम जारी रखूंगा, लेकिन मुझे व्हीलचेयर का उपयोग करना होगा, कम से कम इस (बजट) सत्र के इस भाग में शामिल होने के लिये।” बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होने वाला है।

जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें बुरी नजर लग गई है, तो थरुर ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, “लगे रहने दो (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प.बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस

खड़गे के आवास पर गुरुवार को हुई प्रदेश कांग्रेस की बैठक में हुआ बड़ा फैसला

-श्रीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 5 फरवरी। गठबंधन राजनीति में शामिल रहने के लगभग डेढ़ दशक के बाद, कांग्रेस ने आगामी पश्चिम बंगाल चुनावों में अकेले उतरने का फैसला किया है।

1970 के दशक तक प.बंगाल पर कांग्रेस का प्रभुत्व था पर बाद में धीरे-धीरे कांग्रेस कमजोर होती गई और उसकी खाली जगह पर पहले वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। गठबंधन राजनीति से जुड़ने से कांग्रेस को कोई खास लाभ नहीं हुआ। वर्ष 2011 में, कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और 42 सीटें जीतीं। वर्ष 2016 में, पार्टी ने माकपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा और 44 सीटें जीतीं। पिछले 2021 के चुनावों में, कांग्रेस ने फिर से माकपा नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के साथ गठबंधन किया, लेकिन अपना खाता भी नहीं खोल सकी।

पार्टी के राज्य नेतृत्व की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नई दिल्ली स्थित निवास, 10 राजाजी मार्ग पर गुरुवार को हुई बैठक के बाद “एकला चालो” निर्णय लिया गया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद थे।

बैठक में राज्य के नेताओं ने पार्टी नेतृत्व को बताया कि वाम मोर्चे के साथ गठबंधन से अब खास सफलता नहीं मिल रही है। क्योंकि वाम नेताओं ने कांग्रेस से “संसाधन तो खींचे, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में वोट ट्रांसफर करने में सक्षम नहीं हो सके”। उन्होंने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के साथ चुनावी समझौते को भी नकारात्मक रूप से देखा, क्योंकि

- डेढ़ दशक तक कभी वाम मोर्चा तो कभी तृणमूल के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस का मन लगता है अब भर चुका है।

- गत चुनाव कांग्रेस ने वाम मोर्चा के साथ लड़ा था पर पार्टी का खाता भी नहीं खुला ,इसलिए इस बार वाममोर्चा के साथ कांग्रेस गठबंधन नहीं करना चाहती और तृणमूल पार्टी का रवैया बेहद घमंडी है इसलिए कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी।

- सत्तर के दशक तक बंगाल की राजनीति में कांग्रेस का दबदबा था, धीरे-धीरे पार्टी कमजोर होती गई तो पहले वाम मोर्चा और फिर तृणमूल ने कांग्रेस की छोड़ी हुई जगह हथिया ली।

तृणमूल कांग्रेस का रुख काफी “घमंडी और अक्खड़” था। पिछले विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर पाई, क्योंकि तृणमूल ने कांग्रेस को “बेहद कम” सीटों पर प्रस्ताव दिया था। राज्य के नेताओं ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का यह मत था कि कांग्रेस सिदेबाजी करने की स्थिति में भी नहीं थी। ममता बनर्जी के भतीजे और वरिष्ठ तृणमूल नेता ने यहां तक कि सुझाव दिया था कि कांग्रेस को तृणमूल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बिहार चुनाव में “कैश ट्रांसफर” के मुद्दे पर आज सुनवाई संभव

चुनाव आचार संहिता के दौरान, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दस हजार रु. देने के खिलाफ प्रशांत किशोर ने याचिका दायर की है

- जाल खंबाता -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 5 फरवरी। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित जन सुराज पार्टी ने 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सरकार की कल्याण योजना के दुरुपयोग के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। वह विधानसभा चुनाव रद्द कराने की मांग कर रहे हैं।

किशोर की पार्टी ने 2025 के चुनावों में 243 विधानसभा सीटों में से 242 पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट जीतने में असफल रही। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का मुख्य मुद्दा बिहार सरकार द्वारा चुनावों से ठीक पहले शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने हर परिवार की

- इस योजना के तहत सभी महिलाओं को स्वरोजगार के लिए दस-दस हजार रु. दिए गए थे और वादा किया गया था कि आकलन के बाद काम संतोषप्रद रहा तो 2 लाख रु. और दिए जाएंगे।

- प्रशांत किशोर ने याचिका में आरोप लगाया है कि यह योजना विधानसभा की मंजूरी के बिना मंत्रिमंडलीय फैसले के आधार पर लागू कर दी गई थी और इसके लिए सरकार के आकस्मिक कोष से फंड जुटाया गया, जो संविधान के अनुच्छेद 267 का उल्लंघन था।

- उन्होंने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू था तब 1.56 करोड़ महिलाओं के खातों में दस-दस हजार रु. दिए गए थे, यह “भ्रष्ट आचरण” है।

एक महिला को 10,000 रु. सिधे देने का निर्णय लिया था, ताकि वह स्व-रोजगार शुरू कर सके, साथ ही एक और वादा किया गया 2 लाख रु. का, जो

व्यवसाय का आकलन के बाद दिया जाएगा।

याचिका के अनुसार, इस योजना (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईसाई रीति से हुए विवाहों का रजिस्ट्रेशन करें- हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि ईसाई विवाह अधिनियम के तहत जारी विवाह प्रमाण पत्रों को सिविल रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार नहीं किया जा सकता। यह राज्य का वैधानिक दायित्व है और इसे किसी अधिकारी के विवेकाधीन निर्णय के

- विवाह पंजीकरण नहीं होने से ईसाई दंपतियों को पासपोर्ट, वीजा सहित अन्य सरकारी सेवाओं के लिये कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अधीन नहीं रखा जा सकता। जस्टिस पीएस भाटी और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सिरो-मालाबार रोमन कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट ईचार्ज फादर पॉल पी की ओर से दायर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चुनावों में बढ़ते “रेवड़ी कल्चर” पर सुप्रीम कोर्ट का रुख गंभीर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस विषय पर गंभीर चिंतन की जरूरत है इसलिए इस पर तीन सदस्यीय बैंच विचार करेगी

- जाल खंबाता -

- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 5 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि चुनावी घोषणापत्र और चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त योजनाओं के वादे करने का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। यह सार्वजनिक हित से जुड़े गंभीर सवाल उठाता है और इस पर तीन जजों की बेंच को विचार करना चाहिए।

यह टिप्पणी उस समय की गई जब भाजपा नेता और वकील याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने चुनावी घोषणापत्र और प्रचार के दौरान मुफ्त योजनाओं की घोषणा पर रोक लगाने की मांग की है।

यह संकेत देते हुए कि मामला बड़ी बेंच के सामने रखा जाएगा, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण

- मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा, यह जनहित का गंभीर मुद्दा है और इसे तीन सदस्यीय बैंच द्वारा सुना जाना चाहिए। इसे मार्च में सुना जाएगा तब तक इंतजार कीजिए।

- याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में चुनावों में मुफ्त सामान बांटने के “रेवड़ी कल्चर” पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि 5 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अब सिर्फ सूरज, चांद देने का वायदा किया जाना ही बचा है।

- राजनैतिक दलों ने इस याचिका का विरोध किया तथा इसे राजनैतिक रूप से प्रेरित बताया। उनका कहना है कि लोक कल्याणकारी योजनाएं व सब्सिडी शासन का अस्म भाग हैं इसका लक्ष्य कमजोर तबकों की मदद करना होता है।

- सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में भी सुनवाई के दौरान मुद्दे को जटिल बताया था और अपनी न्यायिक सीमाओं की मजबूरी का उल्लेख किया था।

और सार्वजनिक हित का मामला है...

इसे तीन जजों की बेंच को सुनना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस महीने के बाद मामले की सुनवाई होगी। उन्होंने कहा, “मार्च तक

इंतजार करें।”

उपाध्याय ने अदालत से मामले की तुरंत सुनवाई करने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि आने वाले महीनों में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले

हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल वोटरों को प्रभावित करने के लिए लगातार वादे कर रहे हैं, जो उनके अनुसार भ्रष्ट आचरण है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गुरुवार को ठप्प रही लोकसभा

नयी दिल्ली, 05 फरवरी। लोकसभा में गुरुवार को भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

तीन बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर तीन बजे शुरू होते ही विपक्षी सदस्य फिर से नारेबाजी करने

- लोकसभाध्यक्ष ने दिन भर के लिए कार्यवाही स्थगित करते हुए कहा सदस्य पोस्टर लेकर आएं तो सदन नहीं चलेगा।

लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामे के बीच कहा कि बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि कल कुछ सदस्यों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया और ऐसे दृश्यों का सुजन किया, वह लोकसभा के शुरुआत से लेकर आज तक आज तक कभी नहीं हुआ। संसदीय प्रणाली में सदन के समापति का परिणामय स्थान हमारे संविधान में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दावे ही बाकी रह गए हैं। यह अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अपनी उपलब्धि दिखाने के लिए जोर-शोर से किया गया दावा है। ट्रम्प ने भारत से बहुत बड़ी मांग की थी। वह चाहते थे कि भारत में आने वाले अमेरिकी सामान पर सभी टैरिफ हटा दिए जाएं, जबकि अमेरिका भारतीय उत्पादों पर अपने शुल्क बनाए रखे। सही नहीं कहा जा सकता।

भारत की ओर से इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि अमेरिकी सामान भारत में बिना शुल्क के आएगा। इसके बजाय कुछ बातों से संकेत मिले हैं कि तय कार्यक्रम के अनुसार भारत में आने वाले सामान पर चरणबद्ध तरीके से शुल्क लगाए जाएंगे।

यह संभव नहीं है कि भारत सभी अमेरिकी आयात पर छूट दे, जबकि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- हालांकि, ट्रेड डील को लेकर अभी सिर्फ कयास ही लग रहे हैं लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अमेरिका की दबाव डालने की रणनीति भारत पर कारगर नहीं हुई और यूरोपियन यूनियन के साथ हुई ट्रेड डील से तो अमेरिका की हताशा और बढ़ गई।

- यही वजह रही कि कभी भारत को “डैड इकॉनमी” बताने वाले ट्रंप ने खुद ही ट्रेड डील स्वीकृत करने की घोषणा कर दी क्योंकि ट्रंप समझ गए कि भारत का विशाल बाजार उनके हाथ से निकल रहा है।

- घोषणा अमेरिका की तरफ से हुई और डील भी बेहद आकर्षक थी, ऐसे में भारत के इन्कार करने का सवाल नहीं था।

- पर अब देखना यह है कि वास्तव में यह डील क्या रूप लेती है और भारत को कितना लाभ देगी।

विचार बिन्दु

बच्चों को पालना, उन्हें अच्छे व्यवहार की शिक्षा देना भी सेवाकार्य है, क्योंकि यह उनका जीवन सुखी बनाता है। –स्वामी रामसुखदास

लोकलुभावन नहीं 2047 के भारत की इबारत है नया बजट

संभवतः यह पहला अवसर होगा जब केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करते समय चुनावों में राजनीतिक लाभ हानि पर विचार किये बिना समग्र विकास और दीर्घकालीन आर्थिक सुधार को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया है। कुछ माहों में ही पं. बंगाल, तमिलनाडू, केरल, असम और पुडुचेरी के चुनाव की तिथियां घोषित हो जाएगी। अब तक होता यह आया है कि बजट में चुनाव वाले राज्यों के नागरिकों को लुभाने के लिए खास घोषणाएं होती हैं। पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजनीतिक लाभ हानि के स्थान पर समग्र सुधारों और सरकार के मिशन 2047 को केन्द्र में रखकर 2027-28 का बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वां बजट पेश किया है। खासबात यह कि 2019 से 2026 तक लगातार नवां बजट पेश करने तक वित्त मंत्री सीतारमण भिन्न भिन्न प्रदेशों की हथकरघा साड़ियों में नजर आई है। इस बार तमिलनाडू की बैंगनी कांजीवरम सिल्क साड़ी में नवां बजट पेश किया।

इस साल का बजट इसलिए भी मायने रखता है कि दुनिया के देशों के हालात और वैश्विक परिस्थितियां दिन प्रतिदिन विपरीत होती जा रही हैं। बजट के दिन जहां शेयर बाजार धराशाही हो गया वहीं दूसरे दिन ही अमेरिका द्वारा टैरिफ दर कम करने के साथ ही शेयर बाजार ने उंची उड़ान भर डाली। पर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए भारत की आर्थिक विकास की गति बनाए रखना किसी गंभीर चुनौती से कम नहीं है। विपरीत हालातों में भी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हमारी है। दुनिया के देश जहां आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था ने उंचाई प्राप्त की है। अमेरिका में ट्रंप 2 के बाद से दुनिया के हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं पर जिस रणनीति से भारत ने अमेरिका को इन्फोर की नीति पर चलते हुए चुनौती दी इसी का परिणाम है कि ट्रंप को टेरिफ दरें घटानी पड़ी है। हालांकि ट्रंप के मिजाज को देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब बह पलटी मार जाए।

केन्द्रीय बजट की इसलिए सराहना की जानी चाहिए कि वैश्विक हालातों को देखते हुए दीर्घकालीन आर्थिक सुधार, देश में ढांचगत विकास और युवाओं, महिलाओं, किसानों सभी को साधने का जो समग्र प्रयास हुआ है उससे निश्चित रूप से आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को नई दिशा मिलेगी। विश्लेषक इसे समग्र सुधारों के साथ विकास का संकल्प बता रहे हैं तो कोई इस बजट को भारत की

आत्मनिर्भरता का कवच बता रहे हैं।

कोई इसे एमएसएमई सेक्टर का ग्रोथ इंजन बता रहे हैं तो कोई शी मार्ट के माध्यम से महिला सशक्तिकरण बता रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे तीन कर्तव्यों उत्पादकता को बढ़ावा, आंकाक्षाओं को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास पूरा करने का माध्यम बता रही है। इस बजट में प्राथमिकता लोकलुभावन को नहीं देकर देश को सशक्त आधार देने वाला बनाया गया है। एक और रक्षा बजट को बढ़ाया है। आज दुनिया के जिस तरह के तनाव के हालात बने हुए हैं और हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के हालात हैं, उधर रूस यूक्रेन युद्ध थमने का ही नाम नहीं ले रहा है, ईरान अमेरिका के हालात कब

युद्ध में बदल जाएं कहा नहीं जा सकता है और पाकिस्तान कब अपनी उद्दंडता दिखा दे कुछ कहा नहीं जा सकता, चीन के इरादे हमेशा संदिग्ध रहे हैं ऐसे में रक्षा क्षेत्र में बजटीय प्रावधान बढ़ाना और सैन्य क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाना समय की मांग है। इसी तरह से डिजिटल युग में दुनिया के देशों से दो कदम आगे बढ़ना समय की मांग है। एआई के युग को देखते हुए एआई को रोजगार का माध्यम बनाना, कौशल विकास, तकनीक से शिक्षा को जोड़ने, पर्यटन विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, यहां तक कि गाइड्स तैयार करने से लेकर चुनावों और रोजगार से जुड़े सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के प्रावधान किये गये हैं। खेती-किसानी को प्रोत्साहित करने के साथ ही जल के महत्व को समझा गया है। अमृत सरोवर से जल संग्रहण से लेकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बेहतर लोजिस्टिक प्रमुख आवश्यकता है। रक्षा के बाद सबसे अधिक प्रावधान बेहतर कनेक्टिविटी को दिया गया है। बेहतर आवागमन से विकास को गति मिलती है तो योजनाबद्ध शहरी विकास पर जोर दिया गया है। यदि सार रूप में कहा जाए तो यह बजट आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने का रोडमैप कहा जा सकता है। विनिर्माण क्षेत्र को गति, आधारभूत संरचना विकास, कौशल विवकास, एमएसएमई को प्रोत्साहन, उर्जा विकास व सहज उपलब्धता, इकोसिस्टम बनाए रखते हुए समग्र विकास पर जोर रहा है। हालांकि नौकरी पेशा लोग आयकर में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करने से निराश हुए हैं तो शेयर मार्केट में सर्ट्देबाजी को निरुत्साहित करने से निराशा हुई और इसका तत्काल असर शेयर बाजार पर देखा गया। कहने को लाख आलोचनाएं की जा सकती है पर वैश्विक हालातों को देखते हुए जिस तरह का भविष्योन्मुखी ठोस आधारभूत विकास का बजट होने से इससे दीर्घकालीन लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था को बूस्ट प्राप्त होगा। सबसे खास बात यह है कि इस बजट के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि लोकलुभावन ही नहीं आमजन दीर्घकालीन आर्थिक विकास के बजट का आगे बढ़कर स्वागत करते हैं। अब बजटीय व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन का भी समयबद्ध रोडमैप बन जाए तो निश्चित रूप से इसका वास्तविक लाभ मिल सकेगा।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)

राशिफल

शुक्रवार 6 फरवरी, 2026

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, हस्त नक्षत्र रात्रि 12:2 तक, धृति योग रात्रि 11:37 तक, कौलव करण दिन 12:51 तक, चन्द्रमा आज कन्या राशि में संचार करेगा।

गृहस्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरु-मिथुन, शुक्र-कुम्भ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज कुमार योग सूर्योदय से रात्रि 12:24 तक है।
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:36 तक, लाभ-अमृत 8:36 से 11:19 तक, शुभ 12:41 से 2:03 तक, चर 4:46 से सूर्यास्त तक।

राहुकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:14, सूर्यास्त 6:08



पंडित अनिल शर्मा



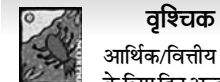
मेघ

परिवार में चल रहे आपसी मतभेद दूर होंगे। अस्त-व्यस्त दिवचार्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



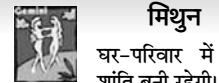
वृष

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



वृश्चिक

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।



मिथुन

घर-परिवार में सुख-शान्ति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।



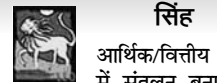
कर्क

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रो/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।



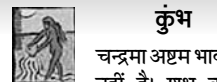
मकर

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



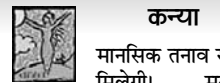
सिंह

आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।



कुंभ

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है।



कन्या

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।



मीन

परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

संपादकीय

ट्रंप डील और मोदी नेतृत्व

राजस्थान के उद्योग के लिए नए अवसरों का द्वार



अशोक परनामी

भारत और अमेरिका के बीच लंबे इंतजार के बाद संपन्न हुई नई ट्रेड डील ने न केवल दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई दी है, बल्कि राजस्थान जैसे निर्यात-आधारित राज्यों के लिए यह समझौता उम्मीदों का नया क्षितिज खोलता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय उत्पादों पर टैरिफ की घटाकर 18 प्रतिशत करने का निर्णय ऐसे समय आया है, जब वैश्विक बाजार में अस्थिरता और संरक्षणवाद

की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। इस प्रष्ठभूमि में यह समझौता भारत की बढ़ती वैश्विक साख और प्रभावी आर्थिक कूटनीति का प्रमाण माना जा रहा है। इस ऐतिहासिक समझौते के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बीते एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद वैश्विक साझेदार के रूप में स्थापित किया है। 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसे अभियानों को अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता दिलाने में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। अमेरिका जैसे प्रभावशाली देश द्वारा टैरिफ में इतनी बड़ी कटौती इस बात का संकेत है कि भारत अब शर्तें तय करने वाली अर्थव्यवस्था बन रहा है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इस डील को 'गेम चेंजर' करार देना भी इसी तथ्य को रेखांकित करता है कि केंद्र के मजबूत नेतृत्व का सीधा लाभ राज्यों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले छह वर्षों में

नौ महत्वपूर्ण ट्रेड डील कर यह साबित किया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब आत्मविश्वास के साथ वैश्विक मंच पर खड़ी है। टैरिफ कटौती का सीधा और तात्कालिक असर राजस्थान के ज्वेलरी, हैडीक्राफ्ट, गारमेंट और स्टोन उद्योगों पर दिखाई देने लगा है। उद्योग संगठनों के अनुसार, टैरिफ बढ़ने के बाद राज्य का निर्यात करीब 50 प्रतिशत तक गिर गया था। कई इकाइयां बंद होने की कगार पर थीं और हजारों कारीगरों व श्रमिकों की आजीविका पर संकट मंडरा रहा था। अब अमेरिकी बाजार से दोबारा पूछताछ और ऑर्डर मिलना शुरू होने से उद्योग जगत में नया उत्साह है।

जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में फैला जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग राजस्थान की वैश्विक पहचान का प्रतीक है। रंगीन पत्थरों और पारंपरिक राजस्थानी डिजाइनों की अंतरराष्ट्रीय मांग टैरिफ वृद्धि के कारण लगभग ठग ही गई थी। उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों का कहना है कि टैरिफ घटने के बाद अमेरिका सहित अन्य बाजारों से मांग लौटने लगी है। इससे कारीगरों और निर्यातकों को नई

ऊर्जा मिली है। अमेरिका जैसे बड़े खरीदार पर काफी हद तक निर्भर स्टोन इंडस्ट्री टैरिफ बढ़ने से सबसे अधिक प्रभावित हुई थी। 70 प्रतिशत से अधिक इकाइयों पर इसका नकारात्मक असर पड़ा। अब टैरिफ कटौती के बाद अमेरिकी खरीदारों की सक्रियता बढ़ने से उत्पादन और रोजगार दोनों में सुधार की उम्मीद है। इसी तरह तीन लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला जयपुर का गारमेंट उद्योग एक बार फिर रफ्तार पकड़ने को तैयार है। निर्यात में गिरावट से जूझ रहे एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से राहतभरा साबित हो रहा है।

राजस्थान का हस्तशिल्प, ब्लू पॉर्टी, लकड़ी का काम, संगमरमर की नक्काशी और हाथ से बने वस्त्र अमेरिकी बाजार में लोकप्रिय रहे हैं। टैरिफ घटने से जयपुर और जोधपुर के कारीगरों को बेहतर दाम और स्थिर बाजार मिलने की संभावना है। यह न केवल आर्थिक लाभ देगा, बल्कि सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी

सहायक होगा। निर्यात में वृद्धि का असर केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा। परिवहन, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, बैंकिंग और बीमा जैसे सहायक क्षेत्रों में भी गतिविधियां बढ़ेंगी। यह 'मल्टीप्लायर इफेक्ट' राजस्थान की अर्थव्यवस्था को व्यापक गति देगा और नए रोजगार सृजित करेगा।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील और टैरिफ में ऐतिहासिक कटौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट दृष्टि और प्रभावी आर्थिक कूटनीति का परिणाम है। राजस्थान के लिए यह समझौता केवल व्यापारिक राहत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ वैश्विक बाजार में आगे बढ़ने का अवसर है। यदि राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों के साथ उद्योग जगत इस अवसर का सही उपयोग करता है, तो राजस्थान आने वाले वर्षों में निर्यात के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकता है और यही इस डील की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।

–अशोक परनामी,
पूर्व विधायक एवं
पूर्व मेयर जयपुर।

तारबंदी से सुरक्षा, बीमा से संबल : किसानों को करोड़ों रुपये का अनुदान मिला

विकसित भारत 2047 के सपने के केंद्र में अन्नदाता : सरकारी सहायता और योजनाओं ने खोले रास्ते, किसान ने दुनिया देखी



अमृता कटारा

भारतीय कृषि को अक्सर परंपरा के फ्रेम में बाँधकर देखा गया है-हल, बैल, मानसून और अनिश्चितता। लेकिन आज खेतों की ज़मीन के नीचे सिर्फ बीज नहीं, बदलाव भी दबाहुआ है। यह बदलाव न तो अचानक है और न ही पूरी तरह दृश्यमान होता है। यह धीरे-धीरे किसान की सोच, नीति और खेती में बदलाव की कोशिश कर रही है। एक ओर रक्षा बजट की कोशिश कर रही है। जिस तरह के तनाव के हालात बने हुए हैं और हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के हालात हैं, उधर रूस यूक्रेन युद्ध थमने का ही नाम नहीं ले रहा है, ईरान अमेरिका के हालात कब

युद्ध में बदल जाएं कहा नहीं जा सकता है और पाकिस्तान कब अपनी उद्दंडता दिखा दे कुछ कहा नहीं जा सकता, चीन के इरादे हमेशा संदिग्ध रहे हैं ऐसे में रक्षा क्षेत्र में बजटीय प्रावधान बढ़ाना और सैन्य क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाना समय की मांग है। इसी तरह से डिजिटल युग में दुनिया के देशों से दो कदम आगे बढ़ना समय की मांग है। एआई के युग को देखते हुए एआई को रोजगार का माध्यम बनाना, कौशल विकास, तकनीक से शिक्षा को जोड़ने, पर्यटन विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, यहां तक कि गाइड्स तैयार करने से लेकर चुनावों और रोजगार से जुड़े सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के प्रावधान किये गये हैं। खेती-किसानी को प्रोत्साहित करने के साथ ही जल के महत्व को समझा गया है। अमृत सरोवर से जल संग्रहण से लेकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बेहतर लोजिस्टिक प्रमुख आवश्यकता है। रक्षा के बाद सबसे अधिक प्रावधान बेहतर कनेक्टिविटी को दिया गया है। बेहतर आवागमन से विकास को गति मिलती है तो योजनाबद्ध शहरी विकास पर जोर दिया गया है। यदि सार रूप में कहा जाए तो यह बजट आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने का रोडमैप कहा जा सकता है। विनिर्माण क्षेत्र को गति, आधारभूत संरचना विकास, कौशल विवकास, एमएसएमई को प्रोत्साहन, उर्जा विकास व सहज उपलब्धता, इकोसिस्टम बनाए रखते हुए समग्र विकास पर जोर रहा है। हालांकि नौकरी पेशा लोग आयकर में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करने से निराश हुए हैं तो शेयर मार्केट में सर्ट्देबाजी को निरुत्साहित करने से निराशा हुई और इसका तत्काल असर शेयर बाजार पर देखा गया। कहने को लाख आलोचनाएं की जा सकती है पर वैश्विक हालातों को देखते हुए जिस तरह का भविष्योन्मुखी ठोस आधारभूत विकास का बजट होने से इससे दीर्घकालीन लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था को बूस्ट प्राप्त होगा। सबसे खास बात यह है कि इस बजट के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि लोकलुभावन ही नहीं आमजन दीर्घकालीन आर्थिक विकास के बजट का आगे बढ़कर स्वागत करते हैं। अब बजटीय व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन का भी समयबद्ध रोडमैप बन जाए तो निश्चित रूप से इसका वास्तविक लाभ मिल सकेगा।

शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कृषि की नीति के केंद्र में रखा है। किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, पीएम-कुसुम, अटल भू-जल योजना, किसान डिजिटल आईडी, तारबंदी और जैविक खेती जैसी योजनाएँ यह संकेत देती हैं कि सरकार ने खेती को अल्पकालिक राहत नहीं, बल्कि दीर्घकालिक योजना मानती है। राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल में लगभग 59 हजार 039 सोलर पंपसेटों की स्थापना कर 900 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया जाना यह बताता है कि सिंचाई और नवीनीकरण ऊर्जा के सवाल को स्थायी समाधान की ओर ले जाया जा रहा है। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 6,450 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम का वितरण यह दर्शाता है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय किसान को आर्थिक सुरक्षा देने का प्रयास किया गया है। खेती में जोखिम कम हुए बिना नवाचार संभव नहीं होता। नीति का असर तब स्पष्ट दिखता है जब वह ज़मीन पर उतरती है।

राजस्थान में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर इस मायने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं। योजनाओं की जानकारी, आवेदन की प्रक्रिया और समस्याओं का समाधान-सब कुछ एक ही मंच पर उपलब्ध होने से किसानों और प्रशासन के बीच की दूरी कम हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि जागरूकता केवल सूचना से नहीं, संवादसे आती है और यही इन शिविरों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रतापगढ़ जैसे जनजाति क्षेत्रों में यह बदलाव विशेष महत्व रखता है, जहाँ खेती लंबे समय तक केवल जीवननिर्वाह तक सीमित रही। छोटी ज़ोतों और सीमित संसाधनों के बीच प्रतापगढ़ के जवाहरनगर के बाबूलाल मीणा द्वारा सरकार की सहायता से वर्मी कम्पोस्ट यूनित की स्थापना यह बताती है कि जैविक खेती अब प्रयोग नहीं रही। कम लागत, बेहतर मूल्य और अतिरिक्त आय-ये



परिणाम बताते हैं कि सही मार्गदर्शन मिलने पर किसान टिकाऊ विकल्पों की ओर बढ़ सकता है। इसी जिले से किसान शंभूलाल पाटीदार का डेनमार्क एक्सपोर्टर विजिट पर जाना यह संकेत देता है कि कृषि प्रशिक्षण अब केवल तकनीक सिखाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोच का दायरा भी बढ़ा रहा है। जब किसान दुनिया को देखने लगता है, तो अपनी ज़मीन को देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। तारबंदी योजना ने भी खेती को स्थिरता दी है एवं किसानों के हितों की रक्षा की है। जवाहरनगर की दुग्धा बाई मीणा और पिल्लू गाँव के पंकज कुमार मीना जैसे किसानों की कहानियाँ यह बताती हैं कि फसल सुरक्षा केवल नुकसान नहीं रोकती बल्कि कृषि को अधिक सुरक्षित बनाती है।

राज्य में लगभग 34,395 किलोमीटर तारबंदी कर 377.66 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाना इस बात का संकेत है कि खेती को जोखिम से मुक्त करने की दिशा में ठोस प्रयास हुए हैं। इसके साथ ही 35,368 फार्म पॉन्ड के निर्माण पर 300 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान जल संरक्षण को खेती की बुनियाद बनाने की मंशा को दर्शाता है। इन सभी अनुभवों और आँकड़ों के साथ रखकर देखा जाए तो स्पष्ट होता

है कि प्रदेश के अन्नदाताओं का भविष्य जनहितैषी कार्यों की निरंतरता, ज़मीनी क्रियान्वयन और किसान की भागीदारी से आकार ले रहा है। खेत आज भी परंपरा से जुड़े हैं, लेकिन अब उनके साथ सुरक्षा, ज्ञान और उम्मीद भी खड़ी है-और शायद यही बदलाव की सबसे बड़ी पहचान है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा कृषि को नवाचार, सुरक्षा और सम्मान से जोड़ने की दिशा में जो व्यापक विजन सामने रखा, उसे राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ज़मीन पर आकार मिलता दिख रहा है। सोलर पंप से लेकर फसल बीमा, तारबंदी से लेकर जल संरक्षण तक-ये प्रयास यह संकेत देते हैं कि किसान को अब केवल उत्पादन की इकाई नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सहभागी माना जा रहा है। जनजाति क्षेत्रों से सामने आई बदलाव की यह कहानियाँ यह भरोसा जगाती हैं कि जब नीति में निरंतरता हो और क्रियान्वयन में संवेदनशीलता, तो खेती केवल अतीत की विरासत नहीं रहती, वह भविष्य की बुनियाद बन जाती है।

शंभू लाल पाटीदार: वैश्विक अनुभव और सरकारी योजनाओं से बदली खेत की तस्वीर

प्रतापगढ़ जिले के प्रगतिशील किसान शंभू लाल पाटीदार ने पारंपरिक

खेती को आधुनिक और लाभकारी कृषि में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी खेती को नई दिशा दी। सरकारी सहयोग से वे पोलिहाउस में लाल और हरी शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें अधिक उत्पादन के साथ बेहतर बाजार मूल्य भी मिल रहा है। उनकी यह सफलता इस बात का उदाहरण है कि सही तरीके से लागू की गई सरकारी योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ टिकाऊ और नवाचारी कृषि को भी बढ़ावा देती है।

हाल ही में शंभू लाल पाटीदार को एक सरकारी कार्यक्रम के तहत डेनमार्क जाने का अवसर मिला, जहाँ उन्होंने उन्नत जैविक खेती की तकनीकों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने इस अनुभव को अत्यंत लाभकारी बताते हुए कहा कि वहां उन्होंने उत्पादन बढ़ाने और खेती में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के कई महत्वपूर्ण गुर सीखे। सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल किसानों को वैश्विक ज्ञान, नई दक्षताएं और नवाचार करने का आत्मविश्वास प्रदान करती है।

–अमृता कटारा,
एपीआरओ, डीआईपीआर

बोर्ड परीक्षाओं के लिए कंट्रोल रूम शुरू

अजमेर, (निर्स)। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के सफल, निष्पक्ष एवं सुचारु आयोजन को लेकर गुरुवार को कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। इस अवसर पर बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठी ने विधि-विधान के साथ मां सरस्वती की पूजा-अर्चना कर कंट्रोल

बोर्ड का शुभारंभ किया। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठी ने जानकारी देते हुए बताया कि कंट्रोल रूम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य परीक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना तथा परीक्षा के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। कंट्रोल रूम

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में स्थापित किया गया है, जहाँ से पूरे प्रदेश की परीक्षा गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठी ने बताया कि कंट्रोल रूम के लिए चार अलग-अलग लैडलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इन नंबरों के माध्यम से प्रदेश भर के परीक्षा केंद्र

अधीक्षक एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी परीक्षा के दौरान आने वाली किसी भी प्रकार की परीक्षा, अव्यवस्था या आपात स्थिति की जानकारी सीधे कंट्रोल बोर्ड को दे सकेंगे। प्राप्त सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बोर्ड प्रशासन का मानना है कि कंट्रोल बोर्ड की सक्रिय

भूमिका से परीक्षा संचालन में पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या तकनीकी समस्या पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सकेगा। इससे न केवल परीक्षा केंद्रों को मार्गदर्शन मिलेगा, बल्कि विद्यार्थियों में भी शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में परीक्षा देने का अवसर मिलेगा।

उदयपुर में बदमाशों ने श्रमिक की हत्या की

मजदूरी पर जाते समय लूट की नियत से श्रमिक को रोक बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया था

उदयपुर, (कासं)। हिरणमगरी थाना क्षेत्र जडाव नर्सरी के समीप गुरूवार सवेरे मजदूरी करने जाते समय लूट की नियत से श्रमिक को रोक बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसका पता चलने पर परिजनों ने हंगामा करते हुए लापरवाह चिकित्सकों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। इस पर सहमति बनने पर मामला शांत हुआ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सविना थाना क्षेत्र विजयसिंह पथिक नगर कच्ची बस्ती निवासी प्रेम गमेली (35) पुत्र मांगीलाल गुरूवार सवेरे हमशरा की तरह मण्डी में मजदूरी करने के लिए जा रहा था। इस दौरान हिरणमगरी थाना क्षेत्र में जडाव नर्सरी

के समीप आए बदमाशों ने लूट की नियत से प्रेम को रोकने पर उसने विरोधक किया तो बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। सूचना पर सविना थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच उसे घायलवस्था में सेटेलाईट चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद एमबी चिकित्सालय ले गए जहां से उपचार के बाद थाने पहुंचे। वहां ज्यादा समय रुकने पर उसकी तबीयत खराब होने पर चिकित्सालय ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर सविना थाना एसआई लादुराम मय टीम ने मौके पर पहुंचकर बदमाशों की तलाश शुरू की। इधर प्रेम की मृत्यु होने कीपर आए परिजनों ने चिकित्सालय में

- परिजनों ने चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया**
- चिकित्सकों के खिलाफ रिपोर्ट देने पर मामला शांत हुआ**

हंगामा करते हुए उपचार में लापरवाही बरतने से मौत के लिए जिम्मेदार चिकित्सकों के खिलाफ कार्यवाही करने, सुआवजा दिलाने, मृतक के परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार देने की मांग करते हुए शव लेने से इनकार

कर दिया। गुरूवार सांय तक कुछ मांगों पर सहमति बनने के बाद मृतक की पत्नी नन्दीनी द्वारा चिकित्सकों के खिलाफ रिपोर्ट देने एवं अन्य मांगों पर मदद का आश्वासन देने पर मामला शांत हुआ। मृतक प्रेम का शव एमबी चिकित्सालय मोचरी में रखा है, जिसका शुक्रवार को पोस्टमार्टम होगा। इधर गुरूवार शाम तक सविना थाना एसआई लादुराम द्वारा मामले में किए गए अनुसंधान घटना स्थल हिरणमगरी पुलिस थाना क्षेत्र होने से वहां प्रकरण ट्रांसफर किया गया।

पिता-पुत्र ने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की : - उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना पुलिस ने पिता-पुत्र व अन्य के खिलाफ बार व रेस्टोरेंट

में घुसकर कर्मचारियों के साथ मारपीट कर तोड़फोड़ करने का प्रकरण दर्ज किया।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित हेमन्त पुत्र लोहरलाल निवासी डागियों का गुड़ा लखावली सुखेर प्रतापगर थाना क्षेत्र में स्थित क्रेजी बार एंड रेस्टोरेंट मैनेजर ने आरोपी हरीश कृपलानी पुत्र आसुमल उसके पुत्र कपील निवासी कन्नामाता अपार्टमेंट तथा अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाया। उसने बताया कि 5 जनवरी सवेरे मेरे रेस्टोरेंट में आए आरोपी व साथियों ने बार में सोए कर्मचारियों पर हमला कर दिया तथा तोड़फोड़ कर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की।

अंतर्राष्ट्रीय हाफ टाइगर मैराथन को मुख्यमंत्री और रणदीप हुड्डा रवाना करेंगे

अलवर, (निसं)। अलवर में आठ फरवरी को आयोजित होने वाली “अलवर की शान-टाइगर थीम” पर अंतर्राष्ट्रीय हाफ टाइगर मैराथन के लिए 18 हजार से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जबकि, मैराथन के लिए दी जाने वाली टी-शर्ट के लिए गुरूवार से धावकों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। इस दौरान उन्हें नंबर के साथ टी-शर्ट भी दी जा रही है। जिला भाजपा मीडिया प्रभारी लक्ष्मीनारायण गुप्ता अंतर्राष्ट्रीय हाफ टाइगर मैराथन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। मैराथन को मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और मैराथन के ब्रांड एंबेसडर अभिनेता रणदीप हुड्डा हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे

यह मैराथन चार श्रेणियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर की

फर्जी दस्तावेजों से चिकित्सालय खोला

उदयपुर, (कासं)। एमबीबीएस छात्र ने अपने दस्तावेजों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर एमपी में चिकित्सालय खोलने वाले के खिलाफ प्रतापनगर पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया।

कृष्णा बिहार पुराना अरटीओ के पास रहेने वाले राजूल प्रताप एस चौहान पुत्र तेजसिंह ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ एमबीबीबीएस दस्तावेजों से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर भोपाल एमपी में चिकित्सालय खोलने वाले के खिलाफ पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। पौडित ने बताया कि 2021 में गुजरात में एमबीबीएस का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एमडी अध्ययन शुरू किया था। 18 दिसंबर को बीमा कंपनी ने एमपी में स्थित चिकित्सालय में उपचाररत रोगी के बीमा क्लेम से संबंध में संपर्क किया। इस पर मैने उसे चिकित्सालय खोलने से इन्कार कर दिया। इसका पता चलने पर प्रतापनगर पुलिस थाने में परिवाद दिया था। इसी को लेकर 3-4 दिन पूर्व दुबारा अन्य मेडिकल बीमा क्लेम में लिए कंपनी प्रतिनिधि ने मुझे फोन कर रोगी के उपचार को लेकर जानकारी मांगी। इस पर मैने दस्तावेज मांगाए, तब कूटरचित दस्तावेज से चिकित्सालय खोले जाने की जानकारी सामने आई।

अवैध हथियार के साथ दो हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

सूरजगढ़ में कोर्ट के बाहर गाड़ी में तोड़फोड़ करने के मामले में कार्रवाई की

पिलानी, (निसं)। स्थानीय पुलिस ने चिड़ावा डीएसटी टीम की मदद से सूरजगढ़ थाने के दो हिस्ट्रीशीटरों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों हिस्ट्रीशीटरों ने अपने चार अन्य साथियों के साथ मिलकर दो दिन पहले ही सूरजगढ़ कोर्ट परिसर के बाहर खड़ी पूर्व पंचायत समिति सदस्य नीरज भंडिया की गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की

- पीलानी पुलिस ने चिड़ावा डीएसटी टीम की मदद से कारवाई कर आरोपियों को पकड़ा**

थी। पुलिस को इस मामले में आरोपियों की तलाश थी।

चिड़ावा डीएसटी प्रभारी एसएसआई शशिकान्त को इत्तला मिली थी कि दो युवक अवैध हथियारों के साथ बेरी इलाके में हैं। जिस पर डीएसटी ने पिलानी पुलिस की मदद से बेरी गांव में पीरुसिंह खेल मैदान के पास नाकाबंद शुरू की। इत्तला के अनुसार ही कुछ देर बाद बेरी गांव की तरफ से एक कैपर गाड़ी आती हुई दिखाई दी। पुलिस की नाकाबंदी को देखकर कैपर सवार युवकों ने गाड़ी को वापस घुमा लिया और अपनी गाड़ी को बेरी गांव की बणी



पिलानी पुलिस ने चिड़ावा डीएसटी टीम की मदद से एक पिस्टल, चार कारतूस और कैपर गाड़ी जब्त की।

की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते की ओर भाग गए, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर गाड़ी रूकवाई, जिसमें सवार सूरजगढ़ थाना इलाके के दोबड़ा निवासी 22 वर्षीय आकाश उर्फ शूटर पुत्र रामसिंह नाई तथा स्वामी सेही निवासी ललित धानक उर्फ लीता पुत्र जसवंत धानक की तलाशी ली गई तो एक अवैध पिस्टल और चार कारतूस मिले। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एक पिस्टल, चार कारतूस और कैपर गाड़ी को जब्त कर लिया है। पूछताछ के दौरान दोनों गिरफ्तार युवकों ने दो दिन पहले सूरजगढ़ कोर्ट के बाहर

गाड़ी से तोड़फोड़ करने की बात स्वीकार की है। गिरफ्तार दोनों युवक सूरजगढ़ थाने के हिस्ट्रीशीटर है। ललित उर्फ लीता के खिलाफ विभिन्न थानों में 10 तथा आकाश उर्फ शूटर के खिलाफ विभिन्न थानों में 15 मामले दर्ज है। सीआई चंद्रभान ने बताया कि दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जिन्हें रिमांड पर लाकर पूछताछ की जाएगी। आरोपियों से और भी मामलों का खुलासा हो सकता है। पिलानी पुलिस द्वारा पूछताछ पूरी होने के बाद आरोपियों को सूरजगढ़ पुलिस तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार करेगी।



पिलानी पुलिस ने चिड़ावा डीएसटी टीम की मदद से एक पिस्टल, चार कारतूस और कैपर गाड़ी जब्त की।

ऑक्सीजन सिलेंडर से भरी लोडिंग टेक्सी की कार से फिर्दत : जोधपुर के बोरानाडा कंटेनर डिपो के सामने एक गंभीर सड़क दुर्घटना हो गई। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा रही लोडिंग टेक्सी और गलत दिशा से आ रही ट्रकवार की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं टेक्सी चालक घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब टेक्सी बोरानाडा इंडस्ट्रियल एरिया की ओर जा रही थी। ट्रकवर इतनी तेज थी कि किया कार के एयरबैग खुल गए, जिससे कार चालक को कोई गंभीर चोट

नहीं आई और वह सुरक्षित रहा। वहीं लोडिंग टेक्सी चालक हैंडल और टेक्सी के बीच बुरी तरह फंस गया। ट्रकवर के बाढ़ टेक्सी का अगला हिस्सा धुक गया, जिससे चालक को बाहर निकालना मुश्किल हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए करीब 15 से 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद टेक्सी का हैंडल तोड़कर चालक को बाहर निकाला। हादसे में टेक्सी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर बोरानाडा पुलिस मौके पर पहुंची।

बैंक में दो-दो सौ के 177 नकली नोट जमा कराए, मामला दर्ज

जानकारी में सामने आया है कि आरोपी सरकारी कर्मचारी बताया जा रहा है

बीकानेर, (निसं)। शहर में नकली नोटों के चलन का मामला सामने आया है। यहां मुरलीधर व्यास नगर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में नकली नोट पहुंचने के बाद नयाशहर थाने में मामला दर्ज कराया है। यहां दो-दो सौ

रुपए के 177 नोट जब्त किए हैं। मुरलीधर व्यास कॉलोनी स्थित भारतीय स्टेट बैंक शाखा में एक खाताधारक ने नगद रुपए जमा कराए हैं। बैंक प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इस मामले में बैंक शाखा प्रबंधक पुरुषार्थ पुरोहित की रिपोर्ट पर नया शहर थाना पुलिस ने श्याम सुंदर नामक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज

- पुलिस को आशंका है कि यह मामला किसी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है**

किया है। यह घटना 2 फरवरी की बताई जा रही है, जब आरोपी ने अपने खाते में 200-200 रुपये के नोट जमा करवाए थे। बैंक में नियमित जांच के दौरान नोट संदिग्ध पाए गए, जिसके बाद मशीनों से जांच कराई गई। जांच में कुल 177 नोट नकली निकले। इसके बाद बैंक अधिकारियों ने नकदी जब्त कर पुलिस को सूचना दी और आवश्यक

दस्तावेज भी पुलिस को सौंपे।

नया शहर थानाधिकारी कविता पुनिया ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी से पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया है कि आरोपी सरकारी कर्मचारी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के पास नकली नोट कहां से आए और क्या इसके पीछे किसी बड़े गिरोह की भूमिका है। पुलिस को आशंका है कि यह मामला किसी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है, इसलिए जांच को गंभीरता से आगे बढ़ाया जा रहा है।

दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान



आग लगने से दुकान में रखा सामान जल गया।

झुंझुनूं, (निसं)। स्थानीय खेमी शक्ति मंदिर के पास समसपुर रोड स्थित शिव मार्केटिंग होलसेल शॉप में बुधवार रात्रि करीब दस बजे अचानक आग लग जाने से दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। फर्म के मालिक रामकरण पायल ने बताया कि वे चंडीगढ़ गए हुए थे। शाम को उनके भाई विजय ने दुकान बंद की थी। रात्रि को करीब 10 बजे

राहगीरों ने दुकान में से धुआं निकलता देखा और उन्होंने आस-पास के घरों में रहने वालों को बताया तो पता चला। इस पर फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस ने पहुंचकर आग बुझाई। आग बिजली के शॉर्ट सर्किट से होने की आशंका है। आग से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया।

अलवर यूआईटी ने अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया



अलवर नगर विकास न्यास की टीम ने कब्जे हटाये।

अलवर, (निसं)। अलवर नगर विकास न्यास (यूआईटी) की अतिक्रमण निरोधक टीम ने बन्ना राम मीणा की जमीन पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया।

नगर विकास न्यास की सचिव धाड़गुडे स्नेहल नाना ने बताया कि ग्राम भूगौर झोपड़ी के खसरा नंबर 645 में करीब एक बीघा कृषि भूमि पर बिना न्यास की स्वीकृति और भू-परिवर्तन कराए ठोवल सड़क बनाकर अवैध प्लॉटिंग और चारदीवारी की जा रही

थी। जमीन पर बन्नाराम मीणा सहित मुकेश, बृजमोहन, महेंद्र, संतोष देवी, छात्राराम व अन्य द्वारा अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जिसे टीम ने तोड़ दिया। इसके अलावा अंबेडकर नगर की वेयरहाउस योजना में सड़क के मुख्य हिस्से पर लगाए गए अवैध खोखे और ठेलों को हटाया गया। वहीं बिना अनुमति की जा रही अवैध ट्रक पार्किंग को भी हटाकर न्यास की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया।

अजमेर के जेएलएन अस्पताल में दुनिया का 43वां दुर्लभ ऑपरेशन सफल

अजमेर, (निसं)। राजस्थान ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जिसने विश्व स्तर पर प्रदेश का मान बढ़ाया है। अजमेर स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने 59 वर्षीय महिला को अत्यंत दुर्लभ बीमारी “एस्ट्रो डुओडेनल इंटुससेप्शन” की सफल सर्जरी कर उसे नया जीवन दिया है। यह मामला न केवल प्रदेश का पहला, बल्कि दुनिया का 43वां और भारत के गिने-चुने दुर्लभतम मामलों में से एक माना जा रहा है।

एक साल का दर्द और अनिश्चितता का हुआ अंत :-जेएलएन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अनिल सामरिया ने बताया कि पाली जिले की निवासी महिला पिछले एक साल से नर्वक जैसा जीवन जी रही थी। भोजन के बाद असहनीय पेट दर्द, लगातार उल्टी, मिचली और गिरते वजन ने उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ दिया था। कई अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद भी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। अंततः परिजनों ने जेएलएन मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ गैस्ट्रो लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉ. अनिल के शर्मा से संपर्क किया। डॉ. शर्मा के नेतृत्व में

- डॉक्टरों ने 59 वर्षीय महिला की अत्यंत दुर्लभ बीमारी “एस्ट्रो डुओडेनल इंटुससेप्शन” की सफल सर्जरी कर नया जीवन दिया**

- यह मामला न केवल प्रदेश का पहला, बल्कि दुनिया का 43वां और भारत के गिने-चुने दुर्लभतम मामलों में से एक माना जा रहा है**

जब एंडोस्कोपी और सीटी स्कैन किया गया, तो आंतों में समस्या के संकेत मिले। सर्जरी के लिए डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी का निर्णय लिया गया। ऑपरेशन टेबल पर जब डॉक्टरों ने जांच की, तो वे भी हैरान रह गए। यह सामान्य समस्या नहीं बल्कि एस्ट्रो डुओडेनल इंटुससेप्शन थी, जिसमें पेट का एक हिस्सा खुद ही आंत के अंदर धंस जाता है।

निजी अस्पतालों में लाखों के खर्च वाली यह जटिल सर्जरी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पूर्णतः नि:शुल्क की गई। डॉ. अनिल शर्मा के साथ डॉ. एमपी शर्मा एंडोस्कोपिस्ट और एनेस्थीसिया टीम का विशेष योगदान रहा। इस केस की दुर्लभता को देखते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय

मेडिकल जर्नल्स में प्रकाशन के लिए भेजा जा रहा है।

डॉ. अनिल के शर्मा, वरिष्ठ सर्जन का कहना है कि हमारा लक्ष्य है कि विश्वस्तरीय चिकित्सा गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। यह सर्जरी हमारी टीम की क्षमता और सेवा भाव का जीवंत प्रमाण है।

डॉ. अरविंद खरे, अध्यक्ष जेएलएन मेडिकल अस्पताल ने जेएलएन मेडिकल कॉलेज टीम को बधाई दी और बताया कि अब राजस्थान के मरीजों को जटिल से जटिल सर्जरी के लिए बड़े महानगरों या विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। अजमेर का जेएलएन मेडिकल कॉलेज अब विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस है।

अनुसूचित जाति आयोग ने आयुक्त कॉलेज शिक्षा को फिर नोटिस भेजा

- पूर्व के तीन नोटिस का जवाब नहीं देने पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नाराज**

प्रोफेसर होने के कारण जैसा कि अन्य महाविद्यालयों में होता है। महाविद्यालय के कार्यवाहक प्राचार्य का चार्ज प्राथी को 19.11.2025 से दिया हुआ था। लेकिन आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के संयुक्त निदेशक एचआरडी डॉ.शोभाराम शर्मा ने 20.11.2025 को अनुसूचित जाति के प्रोफेसर की वरिष्ठता को जानबूझकर नजरअंदाज कर अत्यंत जूनियर डॉ.बनवारी लाल मेनावत को महाविद्यालय चार्ज के आदेश दे दिए। डॉ.मेनावत चयनित प्राचार्य नहीं है जैसा कि भ्रम फैलाया जा रहा है। इनसे मिलीभगत रखने वाले,पक्षपात करने वाले अधिकारियों ने

जयपुर। प्रो. रमेश बैरवा के साथ किए जा रहे सेवा उपीड़न की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने आयुक्त कॉलेज शिक्षा को एक बार फिर नोटिस भेजा है। दिनांक 15 दिसम्बर 2025, 12 जनवरी 2026 एवं 21 जनवारी 2026 को 3 नोटिस आयोग ने जवाब के लिए भेजे थे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की उपनिदेशक अतुलाधा दुसाने द्वारा 4 फरवरी को आयुक्त कॉलेज शिक्षा को भेजे नोटिस में लिखा है कि अपेक्षित सूचना 3 दिन के अनुबंधित समय में नहीं देने को आयोग ने गंभीरता से लिया है। आयुक्त को फिर से आदेशित किया है कि आयोग को अपेक्षित सूचना बिना किसी विलंब के अतिशीघ्र भेजी जाए।ताकि आयोग अध्यक्ष को वास्तविक स्थिति से अवगत कराय़ा जा सके। शिकायत में उल्लेख है कि राजकीय महाविद्यालय गुणपुर सिटी प्राचार्य प्रो.सुमित्रा मीणा ने अवकाश पर जाने के उपरांत कॉलेज के सबसे वरिष्ठ

बैटरी चोर गिरोह का पर्दाफाश

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर की सुभाष नगर थाना पुलिस ने वाहन मालिकों के लिए सिरदर्द बने बैटरी चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 40 से अधिक वाहनों के पास जलदाय विभाग की दो शांतिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार सुभाषनगर थाना प्रभारी कैलाश कुमार दिनेश जाणी ने तत्काल न्यासी ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबि्रों की सूचना पर जात बिछाया। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल मिली, जब उन्होंने दो शांतिर चोर विक्रम सिंह उर्फ मौद् और नरेश उर्फ नन्ू को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार एक फरवरी को राहुल कुमार नामक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

भीलवाड़ा : दूषित पानी पीने को मजबूर हैं बड़ी हरणी गांव के लोग

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के बड़ी हरणी गांव के बाहर हरणी महादेव रोड पर पंचवटी के पास जलदाय विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पिछले करीब एक साल से अधिक पाइप लाइनों के पास स्थित पंचायत में नदी के पानी को लेकर है। पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण बाहर का गंद पानी और कीचड़ पाइपों के भीतर चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रवासियों के घरों में नलों के जरिए दूषित और

लगातार पानी बहने से पूरी सड़क कीचड़ में तब्दील हो चुकी है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों का निकलना दुभ्र हो गया है। सबसे गंभीर स्थिति पेयजल आपूर्ति को लेकर है। पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण बाहर का गंद पानी और कीचड़ पाइपों के भीतर चला जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रवासियों के घरों में नलों के जरिए दूषित और

बदबूदार पानी पहुंच रहा है। स्थानीय निवासी रामपाल सुथार का कहना है कि वे लंबे समय से कीचड़ मिला पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर संकट खड़ा होने की आशंका है। इलाके के लोगों ने रोष प्रकट करते हुए बताया कि दूषित पानी के सेवन से बच्चों और बुजुर्गों में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है।

मुख्यमंत्री ने दो वर्ष की उपलब्धियों के दस्तावेज सदन पटल पर रखे

राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए भजनलाल ने कहा, दो वर्ष में राजस्व घाटा 8000 करोड़ कम किया

जयपुर, 5 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुईं बहस का जवाब देते हुए पहली बार दो वर्ष की उपलब्धियों का दस्तावेज सदन के पटल पर रखा। उन्होंने अपने वक्तव्य में सड़क, बिजली, पानी, कृषि, महिला, युवा कल्याण सहित विभिन्न

■ **“खेजड़ी राजस्थान का कल्पवृक्ष, इसे बचाने के लिये कानून लायेंगे।”**

■ **“देश की 11 जनकल्याणकारी योजनाओं में राजस्थान पहले स्थान पर है।”**

■ **“वर्ष 2023 की तुलना में 2025 में 14.13 प्रतिशत अपराध में कमी आई।”**

क्षेत्रों में वर्तमान सरकार द्वारा दो साल में किए गए कार्यों का तुलनात्मक ब्यूरा सदन के सामने रखा और कहा कि राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था को न केवल स्थिरता दी, बल्कि उसे गति और दिशा भी दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेजड़ी राजस्थान का कल्पवृक्ष भी है, राजस्थान की पहचान भी है, जिसकी बढ ते हुए रेगिस्तान को रोकने में हमेशा सार्थक



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई बहस का जवाब दिया।

भूमिका रही है। शर्मा ने कहा कि हम राज्य के कल्पवृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए कानून भी लाएंगे, जिससे प्रदेश में खेजड़ी संरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने वृक्षारोपण का महाअभियान चलाया और केवल दो वर्षों में 2० करोड़ पौधे लगाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो सालों के कार्यकाल में हमारा प्रदेश 11 जनकल्याणकारी योजनाओं में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। इसी प्रकार 5 राष्ट्रीय योजनाओं में दूसरे स्थान पर और 9 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में तीसरे स्थान के

साथ ही दो प्रमुख आयामों में बेस्ट परफॉर्मर स्टेट का सम्मान हासिल किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को समृद्ध और किसानों को खुशहाल बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। हम पांच साल के भीतर किसान सम्मान निधि को दोगुना करेंगे। दो साल के भीतर ही हम इसे डेढ़ गुना कर चुके हैं।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदमों से वित्त 2 वर्षों से अपराध के ग्राफ में निरन्तर कमी आई है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2025 में

14.13 प्रतिशत अपराधों में कमी दर्ज की गई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर अत्याचार के मामलों में 28 प्रतिशत तथा महिला अपराधों में 1० प्रतिशत की कमी आई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान तो समय पर कर ही रही है, साथ ही, पूर्ववर्ती सरकार की बकाया पेंशन का भी भुगतान किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र के वादे के अनुरूप हमारी सरकार प्रत्येक वर्ष किए गए नीतिगत निर्णय और विकास के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में लेकर जाएगी।

ईसाई रीति से हुए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिणु अदालत ने कहा कि विवाह केवल रिश्ते संबंध नहीं, बल्कि एक वैधानिक स्थिति है। जिससे उत्तराधिकार, सामाजिक सुरक्षा और भरण पोषण सहित अन्य परिणाम उत्पन्न होते हैं।

जनहित याचिका में अधिवक्ता सुसेन मैथ्यू ने अदालत को बताया कि प्रदेश में ईसाई युगल ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 के तहत विवाह करते हैं। इस अधिनियम के तहत विवाह कराने वाले पादरी की ओर से जो विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसे ही पंजीकृत किया जाने का प्रावधान है। इसके बावजूद इन विवाहों को नगर

निगम के रजिस्ट्रार अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम, 2०09 की गलत तरीके से व्याख्या कर पंजीकृत करने में आनाकानी करते हैं।

याचिका में कहा गया कि विवाह पंजीकरण नहीं होने से ईसाई दंपतियों को पासपोर्ट और वीजा सहित अन्य सरकारी सेवाओं के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसे में राज्य सरकार को निर्देश दिए जाए कि वह पादरी को ओर से जारी विवाह प्रमाण पत्रों का पंजीकरण करें।

राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम के प्रावधान ईसाई विवाहों पर लागू नहीं होता है।

इण्डो-यूएस ट्रेड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भारतीय उत्पादों पर 18 प्रतिशत या उससे ज्यादा शुल्क लगाया जाए। अमेरिकी दलों की किसी आधिकारिक ख़ौत से पुष्टि नहीं हुई है। रूसी तेल की भारत द्वारा खरीद के मुद्दे पर आधिकारिक जानकारी सिर्फ़ इतनी है कि भारत वेनेजुएला के सदस्यता हैल के आयात को संभावना पर विचार करने को तैयार है। अगर वेनेजुएला का तेल रूसी तेल से सस्ता होगा, तो भारत के लिए बाढ़ से तेल खरीदना फायदेमंद हो सकता है।

रूस से तेल खरीदने का मुख्य कारण कम कीमत थी।

रूस भारी छूट देकर तेल बेच रहा था क्योंकि दूसरी जगहों पर उसकी बिक्री कम हो रही थी। रूस से तेल खरीदने से भारत का तेल आयात खर्च काफी कम हुआ था।

रूस से तेल खरीद पूरी तरह बंद होने के करीब नहीं हैं। अगर इसमें कोई बड़ी कमी आती भी है, तो उसे लागू होने में कई साल लग सकते हैं।

इस बीच कूटनीतिक स्तर पर भारत और अमेरिकी राष्ट्रपति, दोनों को कुछ न कुछ फायदा मिलता दिख रहा है।

संसद में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रधानमंत्री के जवाब के 3समय की प्रतिक्रिया के बारे में विशेष चर्चा हुई।

बैठक में खड़गे के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में द्रमुक के तिरुवि एन. शिवा, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल वर्मा, शिव सेना उद्धव गुट के अरविंद सावंत, आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन ,इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ईटी बशीर अहमद सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया।

बाद में कांग्रेस संसदीय दल के नेताओं की भी पार्टी के सांसद दल के कार्यालय में बैठक हुई जिसमें गांधी सहित पार्टी के कई नेताओं ने हिस्सा लिया।

प.बंगाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कांग्रेस को एकतरफा समर्थन देना चाहिए। प्रदेश के एक कांग्रेस नेता ने कहा, “यह ठीक है कि आप अपने घर में मजबूत हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरों को कुचल डालों।”

“अकेले चलने के फैसले पर हरी झंडी मिलने की पुष्टि करते हुए, पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के एकमात्र सांसद इशा खान चौधरी ने कहा कि इस फैसले को राहुल गांधी का आशीर्वाद प्राप्त है।

कांग्रेस बंगाल के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने भी इस फैसले की पुष्टि की।

‘दुनिया का सबसे अमीर देश भी घुसपैठियों को निकाल रहा है’

प्रमंत्री मोदी ने तृणमूल पर निशाना साधते हुए कहा कि तृणमूल घुसपैठियों की वकील बन सुप्रीम कोर्ट तक आ गई है

नयी दिल्ली, 05 फरवरी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चुनाव आयोग की मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम और सरकार के आर्थिक सुधारों सहित विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के विरोध पर गुरुवार को राज्य सभा में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की सोच और राजनीति पर तीखे हमले किये। मोदी ने विपक्ष के बहिष्कार के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा का जवाब देते हुए एसआईआर के विरोध के लिए तृणमूल कांग्रेस की आलोचना करते हुए तृणमूल के लोगों को अपने गिरिबों में झांकने की सलाह दी और कहा कि तृणमूल पतन के नये मानदंड बना रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार को निर्मम सरकार बताते हुए कहा कि वह लोगों को भविष्य अंधकार में डाल रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया का सबसे समृद्ध देश भी अपने यहां से गैर कानूनी नागरिकों को निकाल रहा है, लेकिन तृणमूल के लोग घुसपैठियों की

अल-फलाह चेयरमैन सिद्दीकी चार दिन पुलिस हिरासत में

नयी दिल्ली, 05 फरवरी। एक निचली अदालत ने विवादों में घिरे अल-फलाह विश्वविद्यालय के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को कथित धोखाधड़ी और वित्तीय कदाचार के मामले में चार दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

सिद्दीकी को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे आगे की पुछताछ के लिए चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। यह कार्रवाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा दर्ज कराई गई औपचारिक शिकायतों के बाद शुरू की गई है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) ने उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अपराध शाखा ने यूजीसी की शिकायतों के आधार पर सिद्दीकी के खिलाफ दो अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की थीं।

‘सदन में प्रमंत्री के साथ हादसा हो सकता था, मैंने उन्हें सदन में आने के लिए मना किया था’

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया बेहद गंभीर चौंकाने वाला खुलासा

नई दिल्ली, 05 फरवरी। संसद के इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ है जब लोकसभा अध्यक्ष ने खुद यह स्वीकार किया है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और सम्मान को सदन के भीतर ही खतरा था।

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने गुरुार को एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने ही कल (बुधवार) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आने से रोका था। बिड़ला ने आशंका जताई

मेघालय में अवैध कोयला खदान में धमाका, 1 8 मजदूरों की मौत

खदान में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है

शिलांग, 05 फरवरी। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। यहां एक कोयला खदान में हुए धमाके में 18 मजदूरों की मौत हो गई। कई लोग अभी फंसे भी हैं। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुःख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 2–2 लाख रुपए के सहायता राशि की घोषणा की है। पहले इस हादसे में 4 फिर 16 और अब 18 मजदूरों की मौत की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में हुए कोयला खदान विस्फोट पर गहरा दुःख व्यक्त किया, जिसमें कम से कम 16 मजदूरों की मौत हो गई। उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ)

■ **प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर गहरा दुःख जताया, मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रु. व घायलों को 50,०00 रु. देने की घोषणा की।**

ने मोदी के हवाले से एक पोस्ट में कहा, “मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स में हुई दुर्घटना से व्यथित हूं। अपनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।” मोदी ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख

रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,0०0 रुपये दिए जाएंगे।

आधिकारिक रूप से मिली जानकारी के अनुसारमेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में गुरुवार को “अवैध कोयला खदान में विस्फोट होने से कम से कम 16 मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य के फंसे होने की आशंका है। पुलिस महानिदेशक आई नोंगरंग ने यह जानकारी दी। डीजीपी ने बताया कि यह घटना थांगस्कु इलाके में हुई और बचाव दल तलाशी अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा, “हमने अब तक 16 शव बरामद किए हैं, लेकिन विस्फोट के समय खदान के अंदर मौजूद लोगों की संख्या के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है।

‘सदन में प्रमंत्री के साथ हादसा हो सकता था, मैंने उन्हें सदन में आने के लिए मना किया था’

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया बेहद गंभीर चौंकाने वाला खुलासा

■ **ओम बिड़ला ने कहा उन्हें खुफिया जानकारी के साथ सदन के भीतर के हालात से इनपुट मिला था कांग्रेस के सांसद प्रमंत्री के कुर्सी के पास आकर हंगामा कर तथा अनहोनी करने की योजना बना रहे हैं।**

कि अगर पीएम मोदी कल सदन में आते, तो उनके साथ कोई अप्रत्याशित और अग्रिय घटना घट सकती थी।

स्पीकर ने बताया कि उन्हें खुफिया जानकारी और सदन के भीतर के हालात से यह इनपुट मिला था कि

आसाराम के अहमदाबाद आश्रम पर बुलडोजर चलेगा

अहमदाबाद, ०5 फरवरी।

आसाराम का अहमदाबाद स्थित आश्रम टूटेगा। गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को मोटेरा आश्रम ट्रस्ट की तरफ से दायर याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में शहर के मोटेरा इलाके में स्थित भूखंड को खाली कराने की सरकारी कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।

कोर्ट के फैसले से राज्य सरकार के लिए आश्रम की जमीन अपने कब्जे में लेने का रास्ता साफ हो गया है। आश्रम की 45,०00 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन पर 203० कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाना है। वर्तमान में इस जमीन की मार्केट वैल्यू 5०0 करोड़ रुपए से ज्यादा की है।

गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस वैभवनी नानावटी ने इस मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा कि आश्रम में नियमों का उल्लंघन हुआ। उस जगह का विकास परियोजना की जरूरत भी है, इसलिए सरकार की मांग सही है।

इस फैसले के बाद अहमदाबाद नगर निगम कभी भी आश्रम में बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर सकता है।

राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर पब्लिक प्रॉसीक्यूटर जीएच विर्क ने कोर्ट को बताया कि यह जमीन

■ **गुजरात हाईकोर्ट ने आश्रम की जमीन लेने की सरकारी कार्यवाही को सही ठहराया**

दशकों पहले सीमित धार्मिक उपयोग के लिए दी गई थी। लेकिन, धीरे-धीरे इसका विस्तार होता चला गया।

जबकि, भूमि आवंटन की शर्तों के अनुसार इसका व्यावसायिक उपयोग, अनधिकृत निर्माण और बिना अनुमति विस्तार प्रतिबंधित था। आश्रम परिसर में करीब 32 अवैध स्ट्रक्चर बना लिए गए, जो कानूनी सीमाओं से बाहर हैं। उन्होंने बताया कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एएमसी) ने आश्रम को कई बार नोटिस भेजे थे। इसके बाद 21 जनवरी 2०26 को नगर निगम ने आश्रम का आवेदन भी खारिज कर दिया था।

साबरमती नदी किनारे इस आश्रम की स्थापना आसाराम ने 1972 में की थी। आसाराम ने यहां सबसे पहले एक कुटिया बनाई थी, जिसे मोक्ष कुटिया के रूप में पहचाना जाता था। धीरे-धीरे इसी कुटिया के आसपास निर्माण कार्य होता चला गया और बाद में इसे आसाराम मोटेरा आश्रम के नाम से पहचाना जाने लगा।